ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

पलामू उपायुक्त ने करवाया परिंदों के दाना पानी का इंतजाम

रविवारीय, 31 मई - 06 जून 2020 वर्ष- एक, अंक-43, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

कोरोना मरीजों की संख्या दो लाख फिर भी चरमराती अर्थव्यवस्था, बाजार के ध्वस्त होने के भय और लोगों की परेशानी को देखते हुये

शुरू हुआ अनलॉकडाउन

मुख्य संवाददाता

भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहां कोई आसमानी शक्ति अवश्य है जो इस देश को चला रही है और इसके अस्तित्व को बचाये रखे है।

कोविड-19 महामारी के शुरूआत में इसका प्रभाव भारत में बहुत कम था। महज कुछ सौ मरीज ही लंबे समय तक भारत में मिले थे। उस वक्त सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया था। इसके कारण देश में मजदूर और कामगार वर्ग ने भयंकर परेशानियों का समाना किया। दो महिने के लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गयी और अभी दो लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं ? हर रोज सात आठ हजार मरीज मिल रहे हैं और जानकारों की माने तो भारत अब कम्युनिटी ट्रांसफर के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार अगर देश को अनलॉक कर रही है लोग ट्रेनों बसों से भर भर कर अपने गांव पहुंच रहे हैं और संक्रमण को ढो रहे हैं। इन सबके बीच राहत की एकमा। खबर है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है।

लॉकडाउन से संक्रमण रोकने में सफलता मिली या नही ये शोध का विषय है, पर आज जब हालात ज्यादा खराब हैं तब लॉकडाउन में छूट का कारण भी समझा जा सकता है। भारत जैसे अर्द्धविकसित देश को किसी महामारी के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। यहां सिर्फ आर्थिक ही नहीं कई सामाजिक बाधायें भी हैं। पर्व त्यौहारों से लेकर धार्मिक आयोजनों के कारण भी यहां लोग लंबे समय तक लॉकडाउन को नही मानेंगे। साठ दिन के लॉकडाउन के बाद ये तय था कि हालात खराब भी हों पर लॉकडाउन में छूट मिलनी शुरू हो ही जायेगी। प्रधानमंत्री ने कुछ रियायतों की घोषण कर निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। और कुछ क्षेत्रों में छूट की घोषणा होते ही लोग लापरवाही भरी दिनचर्या में लग गये हैं। सरकार भले इसे चरणबद्ध हटाने को कह रही है, पर ये तय है कि लोग संयम और परेशानी के बाद आंशिक छूट में भी लापरवाह होंगे ही और उनमें कोरोना का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है।

क्या पटरी पर लौटेगी जिंदगी ?

64 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।चरण 2 में ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

चरण 3 :अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।

लॉकडाउन में ढील, लेकिन एहतियातों में छूट नहीं: हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में ढील है, लेकिन इन एहतियातों में छूट नहीं है। करबद्ध आग्रह इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। घरों से बिना मास्क कोई भी बाहर नहीं निकलें। सोशल डिस्टेंस के नियमों का पूरा पालन करें। घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। छूट जरूरी चीजों के लिये दी गयी है इसको लापरवाही में न बदलें।

श्रमिकों को झारखंड भेजने में सहयोग करें :मुख्यमंत्री

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने प्रवासी कामगारों को लद्दाख और अंडमान जैसे दुर्गम स्थानों से वापस लाने में ईमानदार प्रयास किया है। अभी भी ऐसे दुर्गम स्थानों में सैकड़ों झारखण्डवासी फंसे हैं।सभी उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो श्रमिक अपने घर वापस आना चाहते हैं, उन्हें झारखण्ड भेजने में राज्य सरकार को सहयोग करें।

झारखंड ने अब तक अपने मजदूरों को सुदूर क्षेत्रों से वापस लाने में सराहनीय पहल की है।प्लेन तक से उन्हें राज्य में लाया गया है।

जानिए झारखंड में क्या-क्या रहेगा खुला
हेमंत सरकार ने किया ऐलान

रांची :देशव्यापी लॉकडाउन।4 के समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने कई छुटों की घोषणा कर दी है। इन छुटों पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र ने अनलॉक -1 के तहत राज्य सरकारों को सौंपा है। इसके तहत राज्य सरकारें यह निर्णय ले सकती है कि किन कामों को करने में छुट होगी और किस पर रोक।

हेमंत सरकार ने इसी अधिकार के तहत झारखंड में भी कई छुटों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित सभी तरह की गतिविधि होगी। जानें किन चीजों को खोलने की मिली अनुमति। यह अनुमति 1 जून से 30 जून तक के लिए दी गयी है।

- मोबाइल सर्विस सेंटर, घड़ी दुकानें, इलेक्ट्रानिक दुकानें,टीवी और कम्यूटंर से संबंधित सभी दुकानें, कॉल सेंटर
- भारी मशीनरी, जनटेरटर, आईटी के हार्डवेयर पाट्स, नेटवर्किंग से संबंधित सामग्री, सॉफ्टेवयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री
- ऑटोमोबाइल सेक्टर
- ज्वेलरी, चश्मे की दुकान, किचन से संबंधित सारी दुकानें,फर्नीचर, गैरज, मोटर वर्कशॉप,
- ग्राहकों को बैठकर नहीं खोलने जाने के शर्त पर रेस्टॉरेंट खोले जाएंगे।
- एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी। रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा।

फूलगोभी की खेती में पोटाश उर्वरक लाभप्रद

डॉ. राकेश कुमार

रांची : सालों भर अनुकूल जलवायु के कारण प्रदेश के किसान सभी मौसम में अधिक गुणवत्ता वाले सब्जियों की खेती करते है। पूर्वी राज्यों की तुलना में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में झारखण्ड प्रदेश का 49।5 प्रतिशत योगदान है। मिट्टी जाँच सर्वे में राज्य के अधिकतर जिलों की भूमि में उपलब्ध पोटाश की उर्वरता का स्तर न्यून से मध्यम पाया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में अंतरराष्ट्रीय पोटाश संस्थान की शोध परियोजना में लत्तीदार सब्जी एवं गोभीवर्गीय सब्जी फसलों पर 3 वर्षो तक पोटाश उर्वरक के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

इस शोध परियोजना के तहत फूलगोभी की खेती में पोटाश के प्रयोग से प्रभाव के अध्ययन के लिए रांची जिले के पिठोरिया एवं ओरमांझी गाँव के किसानों के खेत में प्रत्यक्षण कराया गया। स्थानीय किसानों द्वारा फूलगोभी की खेती में 60 किलो नेत्रजन, 40 किलो स्फूर एवं 20 किलो पोटाश क्रमशः प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार प्रचलित है। जबकि इस प्रत्यक्षण में उर्वरकों की अनूशंषित मात्रा 100 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 60 किलो पोटाश क्रमशः प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया गया। इनमें पोटाश उर्वरक की मात्रा का 100 प्रतिशत और 150 प्रतिशत मात्रा को दो भागों में बाँटकर फूलगोभी की खेती में पोटाश के प्रभाव का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। पोटाश की मात्रा को बुवाई से पूर्व तथा कल्ले निकलने से पूर्व फूलगोभी की खेती में व्यवहार किया गया।

परियोजना अन्वेंशक डॉ राकेश कुमार बताते है कि इस अध्ययन में फूलगोभी का उत्पादन 18।33 से 31।80 टन प्रति हेक्टेयर तक पाया गया। इनमें किसानों में प्रचलित पोटाश सहित उर्वरकों के प्रयोग से न्यूनतम उपज (करीब 18।33 टन प्रति हेक्टेयर) प्राप्त हुई। जबकि 150 प्रतिशत पोटाश उर्वरक के दो बार प्रयोग से अधिकतम उपज 31।80 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ। यानि 150 प्रतिशत पोटाश के दो बार प्रयोग से 16।19 टन प्रति हेक्टेयर अधिक उपज मिला और करीब 43 प्रतिशत औसत उपज में वृद्धि पाई गई। वहीं 100 प्रतिशत पोटाश उर्वरक के दो बार प्रयोग से 29।33 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ।

डॉ राकेश कुमार बताते है कि इस प्रत्यक्षण के आर्थिक विश्लेषण में 100 एवं 150 प्रतिशत पोटाश उर्वरक का फूलगोभी की खेती में दो बार प्रयोग करने से 3।28 लाख से 4।77 लाख किसानों को शुद्ध लाभ मिला। पोटाश के प्रयोग से गोभीवर्गीय सब्जी फसलों की गुणवत्ता बनाये रखते हुए अधिकतम उपज लिया जा सकता है। साथ ही इस तकनीक से किसान भाई परंपरागत फूलगोभी की खेती की अपेक्षा अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते है ।

सीसीएल ने प्रवासी मजदूरों के बीच फूड पैकेट वितरण किया

रांची: :31 मई को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन से आवागमन करने वाले प्रवासी मज़दूरों, छात्रों और अन्य लोगो के बीच फूड पैकेट एवं पानी का बोतल वितरण किया। यह 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन गुजरात से झारखंड के हटिया-रांची रेलवे स्टेशन होते हुऐ देवघर गयी।

सीसीएल के वरीय प्रबंधक(कार्मिक) संजय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने 900 खाने के पैकेट और 900 पानी के बोतल रांची रेलवे स्टेशन के प्रबंधक को सौपा। रेलवे के माध्यम से खाने के पैकेट और पानी के बोतल प्रवासी मज़दूरों, छात्रों और अन्य लोगो के बीच वितरण किया गया । सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व एवं प्रयासों के बल पर सीसीएल अपने कर्तव्यों का पूरी संवदेनशीलता, सजगता और समर्पण के भाव से निर्वहन कर रहा है । कंपनी अपने सीएसआर के अंतर्गत रांची सहित बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा एवं लातेहार जिलों में निरंतर समाज के गरीब, दिहाड़ी मज़दूरो एवं जरुरतमंदो के बीच सूखे राशन की आपूर्ति कर रहा है । बरका सायल, अरगड़ा, उत्तरी कर्णपुरा, राजहरा, पिपरवार, रजरप्पा, कुजू, हजारीबाग, बोकारो एवं करगली, ढोरी, कथारा, मगध एवं अम्रपाली, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में खाद्य सामग्री जैसे चावल, दाल, नमक, आटा, सरसों का तेल, सोया बरी, चूड़ा, मसाले, आलू, प्याज आदि स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध कराया जा रहा है । यह जानकारी विभागाध्यक्ष (जनसंपर्क) सीसीएल ने दी।

हरमु मोक्ष धाम में हुआ गैस आधारित विद्युत शवदाहगृह का सफल परीक्षण

रांची : अंततः हरमु मुक्तिधाम में गैस आधारित शवदाहगृह का सफल परीक्षण कर लिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि अब यहां शवों को दफनाने के लिये लकड़ियों का उपयोग बंद होगा।

ज्ञात हो कि सालों पहले यहां विद्युत शवदाह गृह बनाया गया था, उसके लिये सारे साजो सामान, भवन , इलेक्ट्रिक फर्नेस , अलग से ट्रांसफर्मर भी लगा दिये गये पर यह विद्युत शवदाहगृह चालु नहीं पाया और सब कुछ जर्जर होते गया। ग्रीन रिवोल्ट ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की थी कि क्यों यह शवदाहगृह चालु नहीं हो पाया ?इतने ताम झाम और विवाद के बाद भी हरमु मुक्तिधाम में शवदाह लकड़ी से ही किया जाता है।

हाल में रांची नगर निगम ने इसे फिर से दुरूस्त किया है और एक शव को जला सफलतापूर्वक जला कर देखा गया। अब इसका संचालन मारवाड़ी सहायक समिति के माध्यम से होगा। साथ ही हरमु में सफलतापूर्वक इसके काम करने से अब स्वर्णरेखा तट पर बने विद्युत शवदाह गृह को भी ठिक कर गैस आधारित बनाया जायेगा।

दो छात्रों ने बनाया एग्रीकैप्सूल एग्री नोट्स एप

मुरलीधर

- कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में हैं श्रेया स्नेही और चंदन महली अध्ययनरत
- लॉकडाउन में एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के पठन पाठन उपयोगी
- झारखंड के चार कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

रांची :कोविड -19 की वजह से पूरे देश में दो महीनों से लागू लॉकडाउन से कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की पढाई पर असर पड़ा है। छात्रों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन छात्रों को विभिन्न विषयों के क्लास नोट्स और विस्तृत अध्ययन में परेशानियों झेलना पड़ता था। इसे देखकर रांची कृषि महाविद्यालय के दो छात्रों ने एग्रीकैप्सूल एग्री नोट्स नामक एक एप बनाया है। दोनों छात्रों ने गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर जारी किया है।

इस एप को महाविद्यालय के पांचवे सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र चंदन महली और छात्रा श्रेया स्नेही ने बनाया है। प्रदेश के एकमात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ चार कृषि महाविद्यालय संचालित है। इन महाविद्यालयों के चार सत्रों में करीब 900 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए सभी सामग्री जैसे नोट्स, पाठ्य पुस्तक, मॉडल प्रश्न-पत्र आदि के लिए प्रति दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। छात्रों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए दोनों विद्यार्थियों ने इसे समाहित कर एप बना डाला। इसे शुक्रवार को दोनों छात्रों ने गूगल प्लेस्टोर पर अपलोड कर दिया है। इस एप में आईसीएआर की पांचवी डीन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में लागू एकसमान कृषि स्नातक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर सभी सेमेस्टर के सभी विषयों को शामिल कर किया गया है। एप का नाम एग्रीकैप्सूल एग्री नोट्स है। बोकारो के रहने वाले चंदन महली और पारसनाथ की श्रेयसी स्नेही ने बताया कि पूरे देश में एग्रीकल्चर स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस एप का लाभ मिल सकेगा। इस एप को कोई भी विद्यार्थी गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगे। इस एंड्रॉयड एप में पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित किताबें, लेक्चर नोट्स, पीपीटी और यूट्यूब वीडियो सहित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र को भी अपलोड किया गया है। इसे डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। कई प्रकार के नोट्स के लिए इन दोनों विद्यार्थियों ने अनेकों शिक्षकों व सीनियर विद्यार्थियों से भी मदद ली। एप में एग्रोनोमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, स्वॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टेटेटिक्स आदि विभागों के विषयों से संबंधित पठन सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। विद्यार्थियों ने बताया कि इस एप में 300 से अधिक नोट्स, 15 किताबों के पीडीएफ फाइल, तीन यूट्यूब वीडियो चैनल आदि को अपलोड किया गया है। इसे आगे अपडेट करने की भी कोशिश किया जायेगा। विद्यार्थियों के इस पहल की संकाय के शिक्षकों ने प्रशंसा की।

Agricapsule
Agri Notes

बीएयू के प्रभारी कुलपति सह कृषि सचिव अबु बक्कर सिद्दीक पी ने बीएससी कृषि प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के दो विद्यार्थियों के प्रयासों पर बधाई दी है। इस ऐप से प्रदेश स्थित 4 कृषि महाविद्यालयों और देश के अन्य कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कृषि विषयों का एंड्रॉयड एप से हासिल करने का सरल माध्यम बताया है। डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने कहा है कि दोनों विद्यार्थियों की इस पहल से कृषि स्नातक

टिड्डियों के सामने लाचार

हाल के कुछ महिनों में अदने से जीवों ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया और मनुष्यों को उनकी औकात पर ला दिया है। पहले चमगादड़ों से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करा दिया और अब एशिया के कई देशों को फसल चट कर जाने वाले टिड्डियों के विशाल झुंडो ने तबाह कर रखा है। आशंका जतायी जा रही फसल चट कर जाने वाली इन टिड्डियों के हमले की आशंका झारखंड पर भी जतायी गयी है।

इन पर नियंत्रण के लिये लोग आज भी डीजे बजाने, टीन या ड्रम पीटने जैसे पुराने तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। और हम इस मामले में कितने लापरवाह हैं ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इन विशाल टिड्डी दलों को दवा स्प्रे कर मारने के लिये जो स्प्रे मशीन होती है वह इंग्लैंड से आती है जो इस बार कोरोना संकट के कारण नहीं आ पायी और भारत में इन पर नियंत्रण का काम बाधित हो रहा है। लोग अभी भी शोर करके इन टिड्डियों को भगाने में लगे हुये हैं।

वहीं पाकिस्तान अपने लोगों को टिड्डियों को पकड़ने पर प्रति किलो 12 रूपये दे रहा है और इन टिड्डियों से मुर्गियों का दाना तैयार कर रहा है।

है कि मॉनसून की बारिश के बाद भारत में आये इन टिड्डी दलों की ताकत और बढ़ जायेगी । हाल के कुछ सालों में अरब और अफ्रिका से चलकर पाकिस्तान में तबाही मचा कर आने वाले इन टिड्डियों से देश बचा हुआ था लेकिन इस बार कोरोना संकट ने इनका प्रकोप बढ़ा दिया है।

बताया जा रहा है कि पहले ये टिड्डी दल अरब और अफ्रिका से पनप कर कई देशों से होकर भारत तक पहुंचते थे और इनके झुंडो को उधर के देश ही अपनी फसल बचाने के लिये नियंत्रित कर लेते थे । इससे भारत तक पहुंचते पहुंचते इनका तकरीबन सफाया हो जाता था लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रिका के देशों में टिड्डियों के सफाये पर ध्यान नहीं दिया गया और इनके विशाल झूंड उधर से तबाही मचाते हुये भारत तक आ पहुंचे हैं। इनके नियंत्रण मे एक समस्या और आती है कि इन्हें मारने के लिये ज्यादा जहरीली दवाओं का उपयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे खेत औश्र अनाज के भी बर्बाद होने का डर होता है। इस बार इनका प्रकोप भीषण है और किसान परेशान हैं। पहले इनका हमला पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित था पर इस बार कोरोना संकट में उलझी सरकारों ने शुरूआत में ही इन पर नियंत्रण नही रखा गया इस कारण से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इनके हमलों की आशंका है। महाराष्ट्र तक में इनका हमला देखा गया है। अब कोई मौसमी बदलाव या मानव प्रयास ही इस संकट से फसलों और कृषि को बचा सकता है।

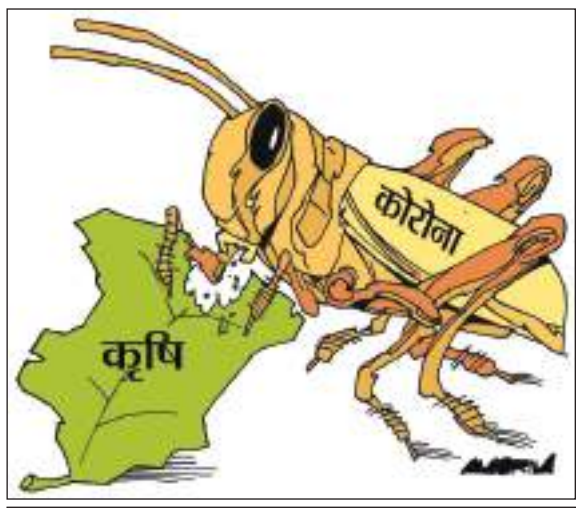

एक कमजोर राष्ट्र से ज्यादा अपेक्षाएं

देवाशिष बसु

निवेश जगत के चतुर लोग जिनके पास वर्षों का अनुभव है, वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरकार अमेरिका और जापान की तरह एक ऐसे वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी जो शायद कारोबारी जगत को मदद पहुंचाएगा। उनकी आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया और बाजार निराशा में डूब गया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगली बार जब फिर ऐसा निराशाजनक माहौल बनेगा तब भी कुछ लोग अपेक्षाएं पाल बैठेंगे। भारतीय राज्य कमजोर रहा है और अभी भी कमजोर है। परंतु इससे हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र में राज्य की क्षमता का आकलन करने में चूक कर सकते हैं जबकि उसमें आंकड़े जुटाना, पुरानी जानकारी निकालना और स्थापित आर्थिक सिद्धांतों को आजमाना होता है तो फिर महामारी जैसे मामलों में क्या होगा जिस-के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

इस सप्ताह सोमवार से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। जल्दी ही रेलवे भी लोगों का समुचित आवागमन शुरू कर देगा। कारोबारी उत्पादन शुरू करने के लिए बेचैन हैं। कोविड लॉकडाउन अभी तक आधिकारिक तौर पर समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मार्च से अब तक तीन बार जनता को संबोधित कर चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक यह नहीं कहा है कि लॉकडाउन समाप्त हो गया है। जाहिर है अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय उनका नहीं है। यह निर्णय विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लेना है। हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि गत दो महीनों में क्या कुछ हुआ।

जब लॉकडाउन लगाया गया और एक अरब लोगों की जिंदगी एकदम ठहर गई तो ढंग से कोई योजना नहीं बनाई गई थी। टेस्टिंग, मास्क, फेस शील्ड, बचाव के अन्य उपकरण, चिकित्सा उपकरण, संपर्कों का पता लगाना आदि कुछ भी ढंग से नहीं किया गया। चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और नगर निकाय कर्मचारी आदि सब बिना किसी खास बचाव के कोविड के हवाले हो गए। जल्दी ही पूरे देश का सामना प्रवासी श्रमिकों के एक बड़े तबके से हुआ। ये लाखों ऐसे लोग थे जो अपने घर परिवार से दूर रोज कमाते-खाते हैं। उनका रोजगार रातोरात छिन गया और वे अपने घरों को वापस जाना चाहते थे। सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी। अगर स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता ने व्यक्तिगत स्तर पर मदद नहीं की होती तो बड़े पैमाने पर लोग भूख से जान गंवा देते। हमारा ध्यान इन बातों से हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने हमें थाली बजाने, ताली बजाने और दीये जलाने को प्रोत्साहित किया। अगर उपरोक्त बातों से कोई संकेत निकलता है तो सवाल यह है कि लॉक-डाउन समाप्त होने को लेकर हमें सरकार से क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए? मुझे आशंका है कि हम तीन तरह से प्रभावित हो सकते हैं।

1. बढ़ते मामले: दुनिया में सबसे कड़े प्रावधानों वाला लॉकडाउन इसलिए लागू किया गया था ताकि महामारी के प्रसार की शृंखला को अवरुद्ध किया जा सके और मामलों का बढना रोका जा सके। हमारे देश में जहां निजी और सार्वजनिक दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है, कोशिश यह थी कि ऐसा करके बड़ी तादाद में मौतों की आशंका को कम किया जा सके। क्या हम इसमें कामयाब रहे? सरकार का आधिकारिक कथन यह है कि हम प्रसार को धीमा करने में कामयाब रहे। नीति आयोग के डॉ वीके पॉल का दावा है कि लॉकडाउन के कारण 14 से 29 लाख संक्रमण कम करने में कामयाबी मिली। जबकि इससे 37,000 से 71,000 मौतें टाली जा सकीं। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रहे कि डॉ वीके पॉल ने गत 24 अप्रैल को जो प्रजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 16 मई तक देश में कोविड के मामले पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जमीनी हकीकत एकदम अलग है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आंकड़े हैं। कई मौतें कोविड से हुई मौत के रूप में दर्ज नहीं हुई हैं और हर राज्य के राजनेताओं के अपने स्वार्थ हैं जिनके चलते गिनती कम हो रही है। इसके बावजूद इसी माह देश में एक दिन में 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अब दोनों बातों को मिलाकर देखें तो देश में मामले बढ़ रहे हैं और हम अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। नतीजा क्या होगा?

2. चरमराता स्वास्थ्य सेवा ढांचा: कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए हर राज्य में स्थानीय प्रशासन ने निजी अस्पतालों तक का अधिग्रहण किया है। खाली बेड की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन हैं और बहुत कम बेड खाली हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि अस्पतालों और हेल्पलाइन के बीच तालमेल नहीं है। ऐसे में जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि बिस्तर खाली नहीं हैं। एक मामले में तो एक कोविड पीड़ित चिकित्सक को पांच घंटे जूझने पर भी अस्पताल में बेड नहीं मिला और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी के मुताबिक पहले उन्हें कहा गया कि नायर अस्पताल में एक बेड खाली है लेकिन बाद में कहा गया कि वहां कोई बेड नहीं है। पूरी मुंबई में उनके पति को एक बेड नहीं मिला। इससे भी बड़ी समस्या गैर कोविड मरीजों के लिए उत्पन्न हुई। एक के बाद एक अस्पतालों में मरीज और चिकित्सक कोविड संक्रमित निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में या तो अस्पताल बंद किया जाता है या फिर मरीज वहां जाना बंद कर देते हैं। जिन मरीजों को नियमित रूप से कीमोथेरेपी या डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना होता है उन्हें दिक्कत हो रही है। जो अस्पताल खुले हैं, उन पर इल्जाम है कि वे मरीजों से बेतहाशा पैसे ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कई निजी अस्पतालों में 31 अगस्त तक बेड अधिग्रहीत किए हैं और उनका शुल्क निर्धारित कर दिया है। मामले बढने पर हालत और खराब होगी।

3. लाइसेंस राज: इसी अखबार के अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित आलेख में कारोबारी नौशाद फोर्ब्स ने चेतावनी दी थी कि कोविड के प्रबंधन के चक्कर में हम लाइसेंस राज की ओर जा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी थी कि हमें अफसरशाही के विशेषाधिकार को केवल रोकथाम वाली जगहों तक सीमित रखना चाहिए। ध्यान रहे कि केंद्र और राज्य अब तक 4,800 से अधिक मशविरे जारी कर चुके हैं।

एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि कोविड के कारण लगे प्रतिबंध पैसे वसूली का बड़ा जरिया हैं और इन्होंने स्वेच्छाचार की राह आसान की है। शहरों के बाहर यह बात खासतौर पर सही है जहां जिलों के अधिकारी और पुलिस अधिकारी सरकारी अधिसूचना की मनमानी व्याख्या करते हैं। कोविड के पहले अगर हमें पता नहीं होता कि सरकार के पास पैसा, इरादे या क्षमता कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं थी लेकिन अब यह सब जानने के बाद अगर हम सरकार से पैकेज या कदम उठाने की मांग करें तो गलती हमारी है।

प्रकृति और हमारे समाधान

कार्बन सिंक में संग्रहीत कार्बन का आकलन व हरित लहर

(डॉ मनोज कुमार)

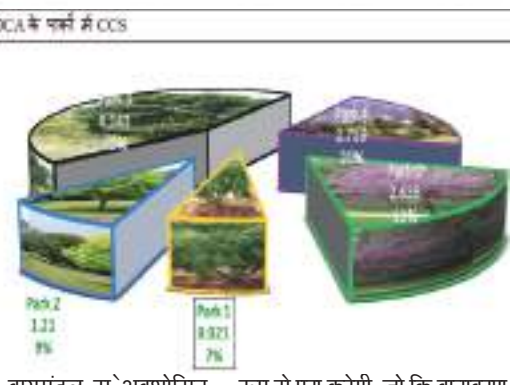

22 मई को पूरी दुनिया ने विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जिसका विषय - हमारे समाधान प्रकृति मेंहै था । यह सप्ताह जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष जैव विविधता सप्ताह एक ऐसे समय पर आया है जब दुनिया को अखंड प्राकृतिक प्रणालियों के महत्व को अधिक समझने की आवश्यकता है और हमारी भलाई प्रकृति की भलाई से जुड़ी हुई है वैसे भी इस बदलते जैव विविधता के कारण मानव का अस्तित्व चाहे वह जलवायु, खाद्य और जल सुरक्षा और स्थायी आजीविका हो हमारी जीवन प्रणाली का आधार प्रकृति आधारित समाधानों पर ही आधारित है ।पर्यावास विनाश, प्रदूषण, भूमि उपयोग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और अस्थिर और अत्यधिक खपत ने जैवविविधता के नुकसान को अत्यधिक प्रभावित किया है।

COVID-19 महामारी के समय जैव विविधता का संबंध भी प्राकृतिक दुनिया की ओर इंगित करता है। एक बात निश्चित है कि हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद, मनुष्य पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य, पानी, भोजन, दवाओं, कपड़े, ईंधन, आश्रय और ऊर्जा के लिए स्वस्थ और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। 2020 अवसर और समाधान का वष है। हम सभी के पास इस बात पर चिंतन करने का अवसर है कि हम इस महामारी से कैसे उबरें और साथ ही साथ समुदायो की लचीलापन बढ़ाने के बेहतर तरीके ढूढ सकें। इस महामारी का कारण जलवाय परिवर्तन भी हो सकता है। समय आ गया है कि स्वच्छ और कुशल ऊर्जा समाधानों, जलवायु नवाचारों के बारे में जागरूकता पैदा किया जाए और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाए जाएं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए मजबूत इच्छा शक्ति अपनाने का समय आ गया है। कार्बन सिंक का उत्तरोत्तर विकास। इस मुहिम को सुदृढ कर सकता है।

बायोम के कार्बन सिंक में संग्रहीत कार्बन का अनुमान लगाने के लिए झारखंड के एक कोयला उत्पादक कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया। कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम कुण्ड है जो वायुमंडल से कार्बन यौगिकों को इकट्ठा और संग्रहीत करता है। बोटकिन, 1993 के अनुसार आम तौर पर बायोमास वृद्धिका वक्र सिग्मोइडल प्रकृति का होता हैअतेव कार्बन पृथक्करण भी उसी आरक्षित प्रकृति का अनुसरण करती है। एक संतुलन बिंदु तक, एक पेड़ द्वारा सौरविकिरण का उपयोग बायोमास वृद्धि और इसके नुकसान के बीच एक संतुलन बनाए रखेगा, और कार्बन भंडारण में कोई वृद्धि, मिट्टी एवं वूडटस्टॉक से ही आएगा। IPCC के अनुसार मृत जैविक पदार्थ जीवित जैव सामग्री में निहित वह बायोमास की मात्रा है जो विघटित हो गया है। बैक्टीरिया और अन्य जीवित जीवों के सक्रियता के कारण ताजा कार्बन स्टॉक वातित परिस्थितियों मे तेजी स विघटित होते हैं। इस शोध (चित्र 1) में 198वृक्षों की 19प्रजातियों को 5श्रेणिओं में विभक्त किया गया और लेखक द्वारा विकसित समीकरण जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई विभिन्न वर्षों के द्विवार्षिक रिपोर्टों और आईपीसीसी द्वारा जारी की गई विभिन्न रिपोर्ट पर आधारित है का उपयोग किया गया। शोध से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र केविभिन्न पार्कों मेंलगभग13.7 ३-CO2e (CCS)का स्टोर संग्रहीत है जिसे वृक्षों ने वायुमंडल स अवशोसित किया है। बृक्षों की गुणवत्ता जैसे लकड़ी, फल, सजावटी, औषधीय और अन्य संबंधित पेड़ों के आधार पर संग्रहीत उउर का अनुपात क्रमशः 7 : 9 : 45 : 20 : 19है (चित्र 2 एवं चित्र 3) । यह परिणाम शोधकर्ताओं एवं प्रबंधकों के लिए अपनेपरिसर में संग्रहीत कार्बन सामग्री (सीसीएस) का अनुमान लगाने और विनियमित करने के लिए एक उपयोगी साधन साबित होंगे ।ऐसा करने में, कोयला कंपनी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UN-FCCC) के उद्देश्य को आंशिक रूप से पूरा करेगी, जो कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता के स्थिरीकरण को प्राप्त करने के लिए है साथ ही जलवायु में मानवजनित हानिकारक हस्तक्षेप को नियंत्रित करेगा। यह अध्ययन प्रबंधित भूमि पर कार्बन प्रवाह की संभावना पर विचार करता है और उनके परिसर में कार्बन सिंक के पूल को मजबूती प्रदान करता है।

अतः आवश्यकता है कि लोग ग्रीन वेव व हरित लहर में भाग लें और इस महामारी के समय जैव विविधता सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं।

अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट के लिए बनेगा कानून

कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए मोदी सरकार जल्द ही दो अध्यादेश लाएगी। इनके जरिए नए केंद्रीय **आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से स्टॉक की सीमा खत्म होगी** कानून के तहत किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी। जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर उपज की स्टॉक सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय कानून को लेकर राज्यों से टकराव की स्थिति का सामना करने की भी तैयारी कर ली है। कृषि मंत्रालय को जल्द से जल्द अध्यादेश संबंधी औपचारिकता पूरी करने के लिए कहा गया है। एक मंत्री के मुताबिक जाहिर तौर पर राज्य का विषय होने के कारण केंद्रीय कानून पर विवाद हो सकता है। मगर किसानों के व्यापक हित में हम इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अध्यादेशों पर छह महीने के अंदर संसद की मंजूरी लेनी होती है। संसद में पारित कानून को ही सांविधानिक रूप से प्रभावी माना जाता है। वैसे मध्यप्रदेश ने किसानों को अपनी उपज किसी भी जगह बेचने की हाल ही में छूट दी है।

पहला अध्यादेश किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार देने वाला होगा। अभी तक किसान राज्यों की ओर से अधिसूचित मंडियों में ही अपनी उपज बेच सकता है। दूसरा अध्यादेश में कृषि उपज के भंडारण की सीमा खत्म होगी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होने के साथ किसानों को सीधा लाभ होगा।

शिमला का सेब पहली बार बिकेगा ऑनलाइन

एपीएमसी ने लिया फैसला

वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे को देखते हुए इस साल पहली बार शिमला का सेब ऑनलाइन बिकेगा। देशभर के खरीदार घर बैठे किसी भी मंडी के सेब की बोली लगा खरीद सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कृषि उपज एवं विपणन समिति (एपीएमसी) शिमला जिले से ऑनलाइन सेब बिक्री की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। हालांकि, देश की पहली ऑनलाइन मंडी सोलन में भी सेब और अन्य फल एवं सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री होती है। एपीएमसी के चेयरमैन नरेश शर्मा ने बताया कि सेब सीजन के दौरान फल मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एपीएमसी ने निर्णय लिया है। ई-नेम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एपीएमसी व्यवस्था करेगा। सेब सीजन के दौरान हर साल चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मद्रास सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में कारोबारी सेब खरीदने शिमला पहुंचते हैं। इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के चलते अगर कारोबारी शिमला नहीं पहुंच पाते तो ऑनलाइन बोली लगाकर सेब खरीद सकेंगे।

ई-नेम पोर्टल से जुड़े हैं 50 हजार किसान-बागवान

सरकार के ई- नेम पोर्टल से 50000 से अधिक किसान-बागवानों को जोड़ा जा चुका है। इनकी उपज की अदायगी भी ऑनलाइन सीधे उनके खातों में की जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सेब सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री खरीदारों और किसान-बागवानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी।

दिल्ली में चल रहे हैं अवैध रंगाई कारखाने

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के बवाना, नरेला, मायापुरी, लिबासपुर और नंगली सकरावत के क्षेत्रों में रंगाई कारखानों के अवैध संचालन पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) की "अधूरी" रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। एनजीटी ने कहा, जिस आंकड़े के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, वह आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है। इस तरह, रिपोर्ट में उल्लेखित निष्कर्ष की सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। एनजीटी ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही रंगाई की 61 इकाइयों की एक विस्तृत सर्वेक्षण कर जांच करने को कहा है, साथ ही इनके अलावा कुछ और इकाईयां जो मानदड़ों का अनुपाल कर रहीं है अथवा नहीं कर रही है उनको भी इसमें शामिल कर 31 अगस्त, 2020 से पहले रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है। न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया तो मुआवजे की वसूली सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

कृषि में आमूलचूल सुधार ही वास्तविक सुधार साबित होंगे

टी. एन. नाइनन

यदि देश के किसानों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी का आकलन किया जाए, जिसमें फसल उत्पादन पर मूल्य समर्थन, उर्वरक, बिजली और पानी की सब्सिडी तथा गत वर्ष शुरू की गई प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपये देने की योजना शामिल है तो यह पूरी राशि 4 लाख करोड़ रुपये अथवा जीडीपी के करीब 2 फीसदी के बराबर होगी। यह तब है जबकि सब्सिडी के कई तत्त्वों को शामिल नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर किसानों के बैंक ऋण पर कम ब्याज दर और समय-समय पर की जाने वाली कर्ज माफी आदि।

चूंकि ये तमाम सब्सिडी और मूल्य समर्थन कार्यक्रम फसली खेती के लिए हैं इसलिए 14 करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन के लिए सरकार की लागत करीब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ती है। यानी दो हेक्टेयर तक के रकबे वाले छोटे किसानों को सालाना लगभग 60,000 रुपये का लाभ मिलता है। अगर आप यह बात किसी किसान से कहेंगे तो वह हंसेगा। चूंकि इसमें इतनी राशि शामिल है इसलिए देश के मेहनतकश लेकिन संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए न्यूनतम आय समर्थन का विचार व्यावहारिक नजर आता है। परंतु केवल तभी जबकि हर तरह की मौजूदा सब्सिडी और मूल्य समर्थन को समाप्त कर दिया जाए। परंतु यह विचार अपने आप में इतना कठोर है कि केंद्र या राज्य का कोई सत्ताधारी दल इस पर शायद ही विचार करे। यही कारण है कि इस माह के आरंभ में कृषि सुधारों के नाम पर मामूली रद्दोबदल देखने को मिला।

वास्तविक सुधारों में पानी के अत्यधिक इस्तेमाल पर लगाम लगाना भी शामिल होगा। पानी का अत्यधिक इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पंप लगाने के लिए बिजली या तो निःशुल्क मिलती है या उस पर भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव में ऐसी क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की संभावना पहले ही खारिज है। ऐसे में आज विनिर्माण क्षेत्र इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त दर चुकाता है। पानी के अतिशय उपयोग को हतोत्साहित करने से पानी की कमी वाले इलाकों मसलन पंजाब में धान

की खेती और महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में गन्ने की खेती पर अंकुश लग सकता है। इससे चीनी और चावल के निर्यात को मिल रही कृत्रिम तेजी को भी खत्म किया जा सकेगा। ऐसे निर्यात पानी का निर्यात करने के समान हैं क्योंकि धान और गन्ने की फसल में सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर, हम देश भर में बढ़ते जल संकट को भी थाम सकते हैं क्योंकि 80 फीसदी पानी का इस्तेमाल खेती में होता है। कड़े सुधारों से अनाज का अतिशय भंडारण भी समाप्त होगा और वह धनराशि बचेगी जो अभी खाद्य सुरक्षा के नाम पर बरबाद हो रही है। इससे खरीद मूल्य को मिलने वाला कृत्रिम बढ़ावा दूर होगा जो गन्ने को देश की सबसे मुनाफे वाली फसल बनाता है। यही कारण है कि हमारे देश में चीनी की उत्पादन लागत विश्व में सबसे अधिक है और देश की चीनी की कीमत शेष विश्व बाजार से 50 फीसदी अधिक है। एक ओर जहां देश के उपभोक्ता इसकी लागत वहन करते हैं, वहीं सरकार को चीनी निर्यात को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की राशि व्यय करनी होती है।

आप कह सकते हैं कि ऐसे समय में जबकि अधिकांश किसान हाशिये पर जीवन बिता रहे हैं और गरीबी के कगार पर हैं, ऐसे में मौजूदा कृषि नीतियों को समाप्त करना बहुत सामान्यीकृत और नुकसान पहुंचाने वाला विचार है। कमोबेश सन 2016 की नोटबंदी की तरह। परंतु इसका यह अर्थ यह नहीं है कि एक कम नुकसानदेह तथा भलीभांति सोचा-विचार और चरणबद्ध बदलाव वाला कार्यक्रम नहीं लागू किया जा सकता। खासतौर पर तब जबकि अंतिम लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि किसानों के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि, किसानों के वास्तविक कल्याण पर ही व्यय हो। उदाहरण के लिए, आज की लागत के एक छोटे हिस्से पर भी एक समझदारी भरी सब्सिडी और मूल्य समर्थन व्यवस्था लागू की जा सकती है और इसके साथ भी सभी किसानों के लिए एक अधिक उदार आय समर्थन योजना के लिए धन बचाया जा सकता है।

सरकार भी यही मानती है कि भारत में आमूलचूल सुधार केवल संकट के दौर में ही अपनाए जा सकते हैं। ऐसे में कोविड संकट को जाया नहीं करना चाहिए। यह सही है कि एक चिकित्सकीय संकट की तुलना आर्थिक नीति सुधार का अवसर देने वाले विदेशी मुद्रा संकट से नहीं की जा सकती है लेकिन यदि सुधार का विचार हो तो ऐसे वास्तविक सुधार लाए जाएं जो सकारात्मक परिणाम देने वाले हों।

राजेंद्र सिंह जी के निधन से अपूर्णीय क्षति :सीसीएल सीएमडी, श्री गोपाल सिंह

रांची : बेरमो विधायक, सीसीएल वृहद् परिवार के वरीय सदस्य एवं श्रमिक संघ के वरिष्ठ नेता स्व. राजेंद्र सिंह जी के निधन से पूरा सीसीएल परिवार आहत है । उनके निधन से न सिर्फ सीसीएल अपितु पूरे कोयलांचल ने एक सच्चा शुभचिंतक व मार्गदर्शक खो दिया है। कोयला कर्मियों के हित के लिए कार्य करने के साथ साथ उन्होंने उनकी सुरक्षा, समस्याओं तथा कंपनी के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरन्तर सीसीएल प्रबंधन के साथ कार्य किया । सीसीएल के सतत विकास में उनका अतुलनीय योगदान रहा है` स्व. राजेंद्र बाबू के साथ मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध लगभग 4 दशक पुराना रहा है, उनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है जिससे मैं मर्माहत हूँ । परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुःख की घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को शक्ति प्रदान करे। सीसीएल वृहद परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

एनजीटी ने जांच के आदेश दिये

आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास पेड़ों की कटाई और अपशिष्ट का निष्कासन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 1 जून को दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर पेड़ों की कटाई के मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अपशिष्ट के उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। यह वही अपशिष्ट है जिसे आनंद विहार के नाले में बहाया जा रहा था।

छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006, के क्रियान्वयन में राज्य के 'वन विभाग' को 'नोडल एजेंसी' का दर्जा दिया गया था। संशोधित आदेश में वन विभाग की भूमिका को पुनः कानून के मूल स्वरूप और दिशा निर्देशों के अनुसार समुदायों द्वारा दावा भरने की प्रक्रिया में समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गयी है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने सरकार द्वारा अपने पिछले आदेश में त्वरित सुधार किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि-'राज्य सरकार ने इस आदेश के माध्यम से वन अधिकार कानून की मूल भावना का सम्मान करते हुए इसके क्रियान्वयन में वन विभाग की भूमिका को न केवल स्पष्ट किया है बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी अधिक स्पष्टता के साथ तय कर दी है।

हरियाणा में धान की खेती पर लगी पाबंदी हटी

हरियाणा सरकार ने लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए धान की खेती पर लगाई पाबंदी हटा लिया है। अब प्रदेश के किसान धान की खेती कर सकेंगे, लेकिन सरकार किसानों को धान की खेती को हतोत्साहित करने के लिए प्रेरित करेगी। किसानों के लिए धान की खेती को स्वैच्छिक कर दिया, लेकिन सरकार ने प्रोत्साहन राशि वाला विकल्प खुला रखा है। पहले जहां किसानों को धान की खेती करने पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए थे, अब सरकार ने उस पर छूट दे दी है।

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की है जरूरत

डॉ सुशील प्रसाद

1 जून, 2020 : विश्व दुग्ध दिवस पर विशेष लेख

प्रत्येक वर्ष पूरे दुनिया में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शूरूआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका, और पोषण के योगदान की महत्ता की ओर जागरूक करना है। इस दिवस को प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ने के लिए मनाया जाता है।

दूध शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, आईरन, पोटैशियम, फोल्लेट्स, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, प्रोटीन, स्वस्थ्य वसा आदि मौजूद होता है। यह बहुत ही उर्जायुक्त आहार होता है। जो शारीर को तुरंत उर्जा उपलब्ध करता है, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन सहित आवश्यक एमिनो एसिड एवं फैटी एसिड मौजूद होता है।

आज विश्वभर में बड़े स्तर पर दुग्ध उपलब्ध हो रहा है। हमारा भारत वर्ष दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 187।75 मेट्रिक टन है और प्रति व्यक्ति खपत करीब 394 ग्राम प्रति दिन है। हमारे झारखण्ड राज्य को करीब 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता है। जबकि झारखण्ड मिल्क फे-डरेशन मेधा डेयरी करीब 1।25 लाख लीटर दुग्ध की आपूर्ति करता है। बाकी 3।77 लाख लीटर दूध का बिहार एवं अन्य राज्यों से आपूर्ति होती है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति 172 ग्राम दूध ही उपलब्ध हो पा रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। प्रदेश को दुग्ध उत्पादन मामले में आत्मनिर्भरता प्रदान कर राज्य के कम से कम 3 लाख परिवारों को रोजगार और आजी-विका मुहैया कराई जा सकती है। इससे राज्य सरकार को भी 8-10 करोड का लाभ होगा। प्रदेश में जिसतरह सब्जी उत्पादन एवं मछली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। उसीतरह किसानों को डेयरी के क्षेत्र में बढ़ावा देने की जरूरत है। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में झारखण्ड 16 वें स्थान पर है, इसमें पंजाब पहले और दमन एवं द्वीव निचले पायदान पर है। एनडीडीआई के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में झारखण्ड में प्रति व्यक्ति 91 मी।ली। प्रतिदिन दूध की उपलब्धता थी, जो अब बढ़कर 172 ग्राम प्रतिदिन हो गया है। केवल दूध उत्पादन के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार का साधन मिल सकता है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन मेधा ब्रांड के नाम से पशुपालकों से दूध इकट्ठा कर प्रोसेसिंग करती है। इससे करीब एक लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े है। करीब 20 हजार पशुपालक सीधे संस्था को दूध दे रहे है। इनके बीच 12 से 15 करोड का भुगतान प्रतिमाह हो रहा है। इस मामले में प्रवासी मजदूर हमारी ताकत हो सकते है। इन्हे तुरंत रोजगार देने का यह सबसे बढ़िया सरल जरिया हो सकता है। इन्हें सरकारी स्तर से दुधारू गाय देकर दुसरे दिन से ही रोजगार का साधन मिलेगा और दूध मामले में अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश में राज्य सरकार और मिल्क फेडरेशन मिलकर जल्द ही तीन प्लांट शुरू करने वाले है। साहेबगंज, सारठ और पलामु में 50 - 50 हजार लीटर दूध का प्रोसेसिंग प्लांट तैयार होने वाला है। इन प्लांट्स के शुरू होने के बाद प्लांट्स को दूध की जरूरत होगी। केवल दुग्ध सेक्टर को थोडा प्रोत्साहित कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाना संभव है। प्रदेश में देशी गाय की दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हरे चारे की खेती को बढ़ावा देकर दूध की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रदेश में अधिक पशु की उपलब्धता बढ़ने से इस व्यवसाय को जैविक खेती से जोड़ा जा सकता है। इससे सरकार की जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास को भी बल मिलेगा।

विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर हमें सु-रक्षित और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशुपालकों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। दूध के महत्त्व पर जागरूकता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव स्वस्थ्य अभियान को बल मिलेगा।

लेखक बीएयू, रांची में डीन वेटनरी हैं

जल निकायों का संरक्षण और पुनर्स्थापन

संवाददाता :नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 1 जून, 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकायों की पहचान, जल निकायों की संख्या, स्थान का विवरण, पानी की गुणवत्ता की स्थिति के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को जानकारी देने का निर्देश दिया है। पहचान किए गए जल निकायों को यदि मरम्मत करने की आवश्यकता है, प्रदूषित जल निकायों की पहचान कर विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशत किया है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक विवरण प्रस्तुत करना होगा। फिर इन रिपोर्टों को सीपीसीबी द्वारा संकलित कर 31 अक्टूबर तक एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। एनजीटी ने अपने आदेश में मौजूदा तालाबों / जल निकायों की क्षमता बढ़ाने, वाटरशेडों के निर्माण की सीमा को बढ़ाने के अलावा कैचमेंट के क्षेत्रों से अत्यधिक बारिश के दौरान पानी जमा करने के महत्व पर जोर दिया। जहां भी जरुरत हो, अतिरिक्त जल निकायों और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए, मनरेगा के तहत उपलब्ध धन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करने का निर्देश दिया है। ग्राम पंचायतें इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और एक बार जब पानी की पर्याप्त क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो उचित जल संचयन तकनीकों का उपयोग करके अतिरिक्त बाढ़ और वर्षा जल को चैनलाइज़ किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को एक महीने के भीतर जिला पर्यावरण योजना या वाटरशेड योजना के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स की बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया था। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर गांव में कम से कम एक जल निकाय बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में की गई कार्रवाई को राज्य स्तर पर संकलित किया जाना था और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। फिर राज्य की एक समेकित रिपोर्ट 31 अगस्त तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जानी चाहिए।

पर्याप्त बिजली , जल आपूर्ति के लिये तैयार रहना होगा: एसोचैम

संवाददाता

एसोचैम ने कहा है कि लॉकडाउन के दरम्यान बिजली और पानी की खपत कम हो गयी है लेकिन अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुलेंगे तक उद्योग धंधों के लिये बिजली और पानी की मांग बढेगी।महासचिव दीपक सूद ने केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि बिजली उत्पादन और वितरण संतोषजनक स्तरों पर बना रहे, क्योंकि देश कई राज्यों में गर्मी की लहर के बीच कोविद -19 महामारी से जूझ रहा है और कुछ क्षेत्रों में पानी की भी कमी है।27 मई को हुए आंकड़ों से पता चलता है कि बढ़ते तापमान और गर्मी की स्थिति ने दैनिक आवश्यकता को 148435 मेगावाट बढा दिया है और उत्पादन 147947 मेगावाट है। 488 मेगावाट की दैनिक कमी के साथ लोग परेशानियों में रह रहे हैं।

इसके बावजूद कार्य स्थल पर होने वाले लॉकडाउन और सख्त मौसम से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को देखते हुए, बिजली उत्पादन, कोयला खनन, परिवहन, वितरण में लगे कर्मी राष्ट्रीय सम्मान के पात्र हैं। ये बातें AS-SOCHAM के महासचिव दीपक सूद ने कही। उन्होंने कहा, कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई राज्यों में जारी गर्मी के मद्देनजर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जल आयोग के आकलन के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में प्रमुख जलाशय में पानी का स्तर अब बेहतर है। लेकिन उत्तरी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में स्थिति आशाजनक नहीं है। यानि कई मायने में चुनौतियां सामने आ रही हैं और हमें उनका सामना करने की जरूरत है।

अब लॉकडाउन के धीरे धीरे खत्म होने से बिजली की मांग औद्योगिक इकाइयों के रूप में बढ़ेगी जो चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह या आंशिक रूप से खुलती जायेंगी। रेलवे और मेट्रो रेल के ट्रांसपोर्ट ग्रिड से बिजली की मांग भी पूरी हो जाएगी। प्रमुख शहरों में, खुदरा मॉल और स्टैंड-अलोन सिनेमा हॉल बंद हैं, यहां तक कि कार्यालय परिसरों में बिजली की खपत भी कम है।

अब जबकि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू करेगा, हमें ज्यादा मांग और सकी आपूर्ति के लिये भी तैयार रहना चाहिए।

विश्व में बेरोजगारी का संकट बढ़ा

एजेंसियां

कोरोनावायरस महामारी ने दुनिया को बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट की ओर धकेल दिया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुमान है कि इस महामारी के कारण दुनियाभर में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कामगारों की 3.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। आईएलओ का कहना है कि यह अनुमान कम से कम है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का अनुमान है कि केवल विकासशील देशों में आय का नुकसान 220 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। अनुमान के मुताबिक, 55 प्रतिशत वैश्विक आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। आर्थिक नुकसान इसे और बढ़ा सकता है।

विश्व बैंक और आईएलओ के अनुमान के मुताबिक, 22 अप्रैल 2020 तक विभिन्न देशों द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण 81 प्रतिशत नियोक्ता प्रभावित हुए। 1 अप्रैल तक विभिन्न देशों में रहने वाले कामगारों को कार्यस्थल बंद करने को कह दिया गया था। हालांकि आगे चलकर यह घटकर 68 प्रतिशत हो गया क्योंकि चीन में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गईं। लेकिन दूसरे देशों में हालात बहुत खराब हो गए। अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित करीब 64 देशों में काम बुरी तरह प्रभावित हुआ।

रेल मंत्रालय की यात्रियों से अपील

भारतीय रेल, देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके । यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं।

ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(अ) दिनांक 17.05.2020 के तहत, अपील करता है की पूर्व ग्रसित बीमारी (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्करोग, कम प्रतिरक्षा) वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से बचें।हम समझ सकते हैं कि देश के कई नागरिक इस समय रेल यात्रा करना चाहते हैं एवं उनको निर्बाध रूप से रेल सेवा मिलती रहे, इस हेतु भारतीय रेल का परिवार चौबीसों घंटे, सातों दिन कार्य कर रहा है। पर हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिकता पड़ने पर कृपया अपने रेल परिवार से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा की तरह तत्पर हैं (हेल्पलाइन नंबर - 139 & 138)

प. बंगाल की जूट मिलों को परिचालन की अनुमति मिली, पर श्रमिक उपलब्ध नहीं

एजेंसियां

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद उद्योग असमंजस में है। मिलों के सामने श्रमबल का संकट है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच करीब 50 प्रतिशत श्रमिक अपने गृह राज्य लौट गए हैं।

केंद्र से मिलों पर लंबित ऑर्डरों को पूरा करने का दबाव पड़ रहा है। जूट मिलों ने शनिवार को कहा कि उन्हें अपने उत्पादन को सामान्य करने में कम से कम दो से तीन सप्ताह का समय लगेगा। वह भी तब जबकि प्रवासी श्रमिक समय पर काम पर लौट आएं। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से मिलें एक जून से 100 प्रतिशत श्रमिकों के साथ परिचालन कर सकती है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता। उद्योग का अनुमान है कि उनका 50 प्रतिशत श्रमबल अपने घरों को लौट गया है।

जूट मिलों में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक झारखंड, बिहार और ओड़िशा के है। लॉकडाउन लंबा खिंचने की वजह से उनकी आमदनी का जरिया बंद हो गया था जिसके बाद वे बसों और लॉरियों में अपने घरों को लौट गए। राज्य की 59 में से ज्यादातर जूट मिलें श्रमिकों को ठेके पर रखती हैं। यानी काम नहीं होने पर उन्हें वेतन नहीं मिलता। एक समूह के प्रवर्तक ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि श्रमिकों ने कामकाज शुरू होने का लंबे समय तक इंतजार किया। शुरुआत में सिर्फ 15 प्रतिशत श्रमबल के साथ परिचालन की अनुमति मिली। ऐसे में जिनको काम नहीं मिल पाया वे अपने घरों को लौट गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के अलावा ईद की वजह से भी काफी श्रमिक अपने गृह राज्य चले गए हैं। राज्य में कई जूट मिलें चलाने वाले समूह के प्रवर्तकों ने कहा कि पूर्ण रूप से परिचालन शुरू करने की अनुमति काफी देर से मिली है। भारतीय जूट मिल संघ के चेयरमैन राघव गुप्ता ने कहा कि बंद के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घर चले गए हैं। ''हमने उनसे 15 दिन में काम पर रिपोर्ट करने को कहा है। अभी हमें इंतजार करना होगा। यह पूछे जाने पर कि बिना उचित सार्वजनिक परिवहन के श्रमिक दूरदराज के क्षेत्रों से कैसे वापस लौटेंगे, गुप्ता ने कहा कि संघ इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाएगा। जूट मिलों के सूत्रों का कहना है कि घर लौटे श्रमिकों को स्थानीय लोगों से बदलना आसान नहीं है क्योंकि जूट मिलों का काम हर कोई नहीं कर सकता।

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि बंगाल के उद्योगों के श्रमबल के संकट को दूर करने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी।

सूक्ष्म पोषक तत्वों का फसलों में उपयोग की आवश्यकता

डॉ.अरविंद कुमार

- **शोध में झारखण्ड की मिट्टी, पौधा व सिंचाई जल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई**
- **बच्चे, पुरूष और महिला के लिए जरूरी उपलब्धता मानक स्तर की कमी**
- **प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए भावी चिंता विषय**
- **आनुवांशिक फसल विकास में जेनेटिक बायोफोर्टीफिकेशन, एग्रोनोमिक बायोफोर्टीफिकेशन एवं मृदा स्वस्थ्य प्रबंधन की हैं जरूरत**

रांची : भारत जैसे विकासशील देशों में मिट्टी और फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आज अपवाद के बजाय एक नियम सा बन गया है। जो फसल की उपज और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जिससे लोग सूक्ष्म पोषक कुपोषण के शिकार हो रहे है। हाल में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विभाग में आईसीएआर-एआ-ईसीआरपी सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रीएन्ट शोध परियोजना के तहत झारखण्ड प्रदेश के 13 जिलों के 126 प्रखंडो में शोध सर्वे किया गया। इस सर्वे में किसान के खेतों की मिट्टी, फसल का पौधा एवं खाने योग्य भाग तथा उपलब्ध सिंचाई का नमूना एकत्र कर प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया। य ह शोध सर्वे रांची, लोहरदगा, खुँटी, रामगढ, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, साहिबगंज, दुमका, गिरिडीह, गढ़वा, कोडरमा एवं गुमला जिलों में चलाया गया। इन जिलों के करीब 30 प्रतिशत भूमि में जिंक की कमी पाई गई है। प्रदेश के दुमका, रांची, गुमला एवं लोहरदगा जिले में 56 - 64 प्रतिशत तक भूमि में बोरोन एवं गंधक की कमी पाई गई है। जबकि अन्य जिलों की मिट्टी में 40 - 45 प्रतिशत तक कमी पाई गई है। वहीं मिट्टी में जिंक, कॉपर, आयरन व मैंगनीज की उपलब्धता संतोषप्रद पाया गया है।

किसानों के खेत में लगे टमाटर, मटर, अरहर, आलु, सरसों, अदरख, प्याज, सेम एवं गाजर के खाने योग्य भाग के नमूनों की जाँच में जिंक, कॉपर, आयरन व मैंगनीज की उपलब्धता समुचित मात्रा में नहीं पाया गया है। यह उपलब्धता 10 वर्षो तक उम्र वाले बच्चों, 10 वर्षो से अधिक पुरूष एवं महिला के लिए आवश्यक प्रतिदिन की मानक मात्रा से काफी कम देखा गया है। सर्वे में सिंचाई जल की जाँच में आयरन, जिंक, कॉपर और बोरोन की उपलब्धता मानक क्रांतिक अवस्था से काफी कम पाया गया है।

परियोजना अन्वेंशक डॉ अरविन्द कुमार बताते है कि खाने योग्य भाग में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मिट्टी से पौधों में स्थानांतरण नहीं होना कारण है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का पौधों के आनुवांशिक विकास में उपलब्धता बढ़ाने के लिए जेनेटिक बायोफोर्टीफिकेशन, एग्रोनोमिक बायोफोर्टीफिकेशन एवं मृदा स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। फसल उत्पादकता में सुधार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व और आवश्यकता के बारे में प्रदेश के किसानों में जागरूकता बहुत सीमित है। इस ओर राज्य सरकार और प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा ज्ञान प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत हैं।

फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताएं कम मात्रा में होती हैं। परंतु इनकी कमी के कारण उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगाई गई फसलों में इन पोषक तत्वों का अभाव होने के कारण मानव शरीर को भी कुपोषण का शिकार बनाता है। इसलिए खेत की मिट्टी की जांच के बाद सूक्ष्म तत्वों का उपयोग इनकी कमी की अवस्था में मिट्टी में डालकर या स्प्रे के माध्यम से पूर्ति कर निदान किया जा सकता है।

डॉ अरविन्द बताते है कि देश में पिछले 10 वर्षो में सूक्ष्म पोषक तत्वों की खपत में अच्छी वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धि प्रदेश में काफी न्यून है। फसलों में सूक्ष्म तत्वों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग की पहल से फसल की पैदावार और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

फोटो न्यूज

पलामू उपायुक्त शांतनु अग्रहरि की परिंदों के लिये अनोखी पहल

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पक्षियों को प्रतिदिन मिलेगा दाना-पानी

पलामू में बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पलामू जिला प्रशासन ने बेजुबान पक्षियों के लिए भी दाना-पानी का इंतजाम करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गर्मी के कारण पक्षियों के समक्ष दाना और पानी की समस्या नहीं रहे इसके लिए उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि के निदेश पर पलामू जिला प्रशासन नगर निगम की सहयोग से पक्षियों को प्रतिदिन दाना-पानी उपलब्ध करायेगा। इसमें निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षदों का अहम योगदान होगा। पक्षियों को प्रतिदिन दाना-पानी रखने हेतु प्रति वार्ड 3(तीन) खुला पिंजड़ा उपलब्ध कराये गये हैं।मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्ड हेतु 3(तीन) की दर से 105 निःशुल्क खुला पिंजड़ा उपलब्ध कराया गया है।

उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने पक्षियों के लिए दाना -पानी रखने की दिशा में शुरू की गई इस पहल को और बृहद रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गर्मी के दिनों में पक्षी ज्यादा छायादार स्थान एवं दाना खाने-पीने के लिए पानी की तलाश में रहते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने खुला पिंजड़ा बनवाकर वार्डो को उपलब्ध कराया है। ऐसे में हमलोग दाना-पानी रखकर परिंदों की जान बचाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। सभी की सहभागिता से पक्षियों को दाना-पानी उपल्बध हो सकेगा और उन्हें इधर-उधर भटकने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम पक्षियों के जीवन का संरक्षण करें। दाना-पानी रखकर पक्षियों के जीवन बचाने के लिए पहल करें।

माइग्रेन : समस्या और उसका समाधान

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

माइग्रेन या अधकपारी सर दर्द का एक प्रकार है जिसमें मध्यम से गंभीर दर्द होता है। ये दर्द आधे सिर में होता है या सिर के एक हिस्से को ज्यादा प्रभावित करता है।विश्व में लगभग 15%-20% लोग अधकपारी की समस्या से ग्रस्त हैं। कुछ लोगों को उल्टी , सरदर्द आदि की परेशानी भी होती है।पुरषों से ज्यादा ये समस्या महिलाओं में पाया जाता है। अधिकतर लोग इसे एक मामूली बीमारी समझ के दर्द की दवा ले लेते हैं जिससे सिर्फ कुछ समय के लिए आराम होता है परन्तु अगर इसका उपचार सही हो तो हमेशा के लिए राहत मिल सकती है।अपने दर्द के प्रतिरूप को जाने, दर्द कब होता है और इसकी आवृत्ति क्या है ,इसके बाद हम दर्द का उपचार कर सकते हैं।

अपने जीवनशैली का अध्ययन करें और देखें कि किन कारणों से आपको बार-बार दर्द हो रहा है।आप उन दिनों को नोट करना शुरू करें जिस दिन आपको दर्द हुआ था और फिर देखें कि उन सभी दिनों में क्या समानताएं थी। उदाहरण के रूप में अगर ये दर्द आपको हर सोमवार को हो रहा है और आप रविवार को देर तक जागते हैं ,तो नींद की कमी इसका कारण हो सकता है।

ठीक ऐसे ही आप अपने दर्द का कारण पता कर सकते हैं। माइग्रेन के कुछ निम्न कारण भी हो सकते है।

- ✓देर रात तक जागना।
- ✓ठीक समय पर खाना न खाना।
- ✓ज्यादा तनाव में रहना।
- ✓घुम्रपान करना।
- ✓हॉमोर्न में बदलाव।
- ✓असमयित मासिक धर्म होना।
- ✓मौसम में अचानक बदलाव।
- ✓बहुत देर तक धूप में रहना।
- ✓बहुत देर तक कम्प्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करना।

जब आपको दर्द की वजह पता चल जाऐ तो आप इसका निवारण कर सकते हैं। माइग्रेन से बचाव के लिए एक अच्छी जीवनशैली का होना जरूरी है।
स्वस्थ रहने के निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

- ✓समय पर सोना और उठना।
- ✓सेहतमंद खाना खाना।
- ✓योगा और प्राणायाम को अपनी आदत में शामिल करना।
- ✓खुश रहना और तनाव कम करना।

अगर दर्द काफी ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें।

प्रतिदिन योगा और प्राणायाम करने से भी माइग्रेन में काफी राहत मिलती है। योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने से और भी कई बिमारियों में काफी लाभ मिलता है। माइग्रेन से बचाव के लिए योगा आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी के लिए instagram पर फ़ॉलो करें। Ritusinghfitness.

इसमे हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें। ritusinghfitness.

बारिश का पूर्व सूचक अमलतास

देवाशीष

अमलताश सुंदर पीले फूलो वाला एक फूलों वाला वृक्ष है। अमलतास को संस्कृत में व्याधिघात, नृप्रद्रुम, आरग्वध, कर्णिकार इत्यादि, मराठी में बहावा, कर्णिकार गुजराती में गरमाष्ठो, बँगला में सोनालू तथा लैटिन में कैसिया फ़स्चिुला कहते हैं। शब्दसागर के अनुसार हिंदी शब्द अमलतास संस्कृत अम्ल (खट्टा) से निकला है। भारत में इसके वृक्ष प्रायः सब प्रदेशों में मिलते हैं। तने की परिधि तीन से पाँच कदम तक होती है, किंतु वृक्ष बहुत उँचे नहीं होते। अप्रैल, मई में पूरा पेड़ पिले फुलों के लंबे लंबे गुच्छों से भर जाता है। और ऐसा माना जाता है कि फूल खिलने के बाद 45 दिन में बारिश होती हैं। इस कारण इसे गोल्डन शॉवर ट्री, और इंडियन रेन इंडिकेटर ट्री भी कहा जाता हैं। शीतकाल में इसमें लगनेवाली, हाथ सवा हाथ लंबी, बेलनाकार काले रंग की फलियाँ पकती हैं। इन फलियों के अंदर कई कक्ष होते हैं जिनमें काला, लसदार, पदार्थ भरा रहता है। वृक्ष की शाखाओं को छीलने से उनमें से भी लाल रस निकलता है जो जमकर गोंद के समान हो जाता है। फलियों से मधुर, गंधयुक्त, पीले रंग का उड़नशील तेल मिलता है।

पानी से जहरीले क्रोमियम को अलग करने वाला स्पंज बनाने का प्रयास

क्रोमियम से डीएनए को भारी नुकसान पहुंचता है और यह कैंसर के ट्यूमर का निर्माण करता है। हेक्सावलेंट क्रोमियम दुनिया भर के जल स्त्रोतों को दूषित करता है, यह अत्यंत विषैला माना जाता है। सांस लेने या निगलने जाने से यह जान तक ले सकता है। इसका उपयोग करने के लिए यूरोप और दुनिया भर के कई देशों ने कठोर नियम बनाए है। यह कैंसर के ट्यूमर का निर्माण करता है। हेक्सावलेंट क्रोमियम केमिकल का उपयोग चमड़ा उद्योग, क्रोमियम की परत चढ़ाने, रंगीन कांच बनाने और पेंट पिगमेंट और स्याही में होता है। यह अक्सर पानी के साथ बहकर जल स्त्रोतों तक पहुंच जाता है तथा उन्हें प्रदूषित करता है।

स्विट्जरलैंड के इकोले पॉलीटेक्निक फेडरेल डे लौसैन (ईपीएफएल) के रसायनज्ञ पानी से, इस हेक्सावलेंट क्रोमियम, प्रदूषण को दूर करने के लिए कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण विकसित कर रहे हैं। दुनिया भर में सभी को स्वच्छ पानी प्रदान करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तेजी से पानी के प्रदूषण को दूर करने में सक्षम ऐसे उपकरण का विकास करना, वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह शोध जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री ए में प्रकाशित हुआ है।

क्वीन और सहकर्मी स्पंज जैसी एक सामग्री विकसित कर रहे हैं जो मिश्रण से विशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर अलग कर सकते हैं। ये पदार्थ वास्तव में क्रिस्टल हैं, जिन्हें धातु-कार्बनिक ढांचा भी कहा जाता है, और वैज्ञानिक इस विशेष पदार्थ की मदद से पानी से जहरीले पदार्थों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सामग्री अत्यधिक छिद्रयुक्त होती हैं और इसकी सतह का क्षेत्र एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो सकता है। दूषित पदार्थ तब इन छिद्रों में प्रवेश करता है और सोखने की प्रक्रिया के दौरान आंतरिक सतह से चिपक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी दिखाया कि उनका यह उपकरण अन्य पदार्थों के मिश्रण जैसे सोना, पारा और सीसे को सोख कर अलग कर सकता है।

महाविनाश की सच्चाई आई सामने

6.6 करोड़ साल पहले हुए महाविनाश की सच्चाई आई सामने, जानें कैसे खत्म हुआ डायनासोर का वजूद

- क्षुद्रग्रह का मॉडल बनाकर किया अध्ययन
- 60 डिग्री कोण पर हुई टक्कर से मची थी ज्यादा तबाही
- वैज्ञानिकों ने किया सिमस्यूलेशन अध्ययन

एजेंसियां

नई दिल्ली : एक समय ऐसा था जब धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज था, लेकिन आज उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की वजह से उसका अंत हुआ है। 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर हुए इसी महाविनाश को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। जिसमें बताया कि कैसे ये विशालकाय जीव अचानक गायब हो गए और धरती से एक युग का अंत हो गया। नेचर कम्यूनिकेशन्स में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने क्रेटर का अध्ययन कर सिमस्यूलेशन के जरिए क्षुद्रग्रह और पृथ्वी के बीच हुई महाटक्कर को समझने की कोशिश की। इसमें पता चला कि क्षुद्रग्रह उत्तरपूर्वी दिशा से आया था। यह पृथ्वी की सतह पर क्षितिज से 60 डिग्री के कोण से टकराया था। इस कोण की वजह से सर्वाधिक मात्रा में गैस वायुमंडल में फैल गई। इसी का असर पूरी पृथ्वी की जलवायु पर पड़ा।

75 प्रतिशत जीवन हो गया था खत्म

वैज्ञानिकों के अनुसार 6.6 करोड़ साल पहले घटी इस घटना से मेसोजोइक युग एक झटके में खत्म हो गया था। इससे पूरी पृथ्वी का 75 प्रतिशत जीवन खत्म हो गया। इसमें डायनासोर की सभी प्रजातियां शामिल थीं। क्षुद्रग्रह और पृथ्वी के बीच हुई खतरनाक टक्कर से धरती पर विशाल गड्ढे भी बनें। जिन्हें क्रेटर कहते हैं। मैक्सिको के यूकाटान प्रायद्वीप में एक गोल इलाका है। जिसे चिक्सूलुब क्रेटरकहा जाता है। यह 200 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यह क्रेटर उसी टक्कर से बना था।

शोधकर्ताओं ने सिम्यूलेशन के जरिए 17 किलोमीटर के व्यास का एक क्षुद्रग्रह का मॉडल बनाया। जिसका घनत्व उन्होंने 2.630 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रखा। इस सिम्यूलेशन में उन्होंने इसे 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने क्रेटर के कुछ असामान्य हिस्सों का भी अध्ययन किया जो करीब 30 किलोमीटर तक गहरे थे। इससे उन्होंने टक्कर के समय क्षुद्रग्रह की दिशा और उसके कोण का अनुमान लगाया।

छींकने पर 20 फुट तक पहुंचता है कोरोना वायरस

एजेंसियां :एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक-दूसरे से छह फुट की दूरी बनाने का नियम नाकाफी है, क्योंकि यह जानलेवा वायरस छींकने या खांसने से करीब 20 फुट की दूरी तक जा सकता है।

वैज्ञानिकों ने विभिन्न वातावरण की स्थितियों में खांसने, छींकने और सांस छोड़ने के दौरान निकलने वाली संक्रामक बूंदों के प्रसार का मॉडल तैयार किया है और पाया कि कोरोना वायरस सर्दी और नमी वाले मौसम में तीन गुना तक फैल सकता है। इन शोधार्थियों में अमेरिका के सांता बारबरा स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी शामिल हैं। उनके मुताबिक, छींकने या खांसने के दौरान निकली संक्रामक बूंदें विषाणु को 20 फुट की दूरी तक ले जा सकती हैं। लिहाजा, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मौजूदा छह फुट की सामाजिक दूरी का नियम अपर्याप्त है।

पिछले शोध के आधार पर उन्होंने बताया कि छींकने, खांसने और यहां तक कि सामान्य बातचीत से करीब 40,000 बूंदें निकल सकती हैं। यह बूंदें प्रति सेकंड में कुछ मीटर से लेकर कुछ सौ मीटर दूर तक जा सकती हैं। इन पिछले

अध्ययन को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि बूंदों की वायुगतिकी, गर्मी और पर्यावरण के साथ उनके बदलाव की प्रक्रिया वायरस के प्रसार की प्रभावशीलता निर्धारित कर सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि श्वसन बूंदों के माध्यम से कोविड-19 का संचरण मार्ग कम दूरी की बूंदें और लंबी दूरी के एरोसोल कणों में विभाजित है।

अध्ययन में कहा गया है कि बड़ी बूंदें गुरुत्वाकर्षण के कारण आमतौर पर किसी चीज पर जम जाती हैं जबकि छोटी बूंदें, एरोसोल कणों को बनाने के लिए तेजी से वाष्पित हो जाती हैं, ये कण वायरस ले जाने में सक्षम होते हैं और घंटों तक हवा में घूमते हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक, मौसम का प्रभाव भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि कम तापमान और उच्च आर्द्रता बूंदों के जरिए होने वाले संचरण में मददगार होती है जबकि उच्च तापमान और कम आर्द्रता छोटे एरोसोल-कणों को बनाने में सहायक होता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में लिखा है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा अनुशंसित छह फुट की दूरी वातावरण की कुछ स्थितियों में अपर्याप्त हो सकती है, क्योंकि ठंडे और आर्द्र मौसम में छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाली बूंदें छह मीटर (19.7 फुट) दूर तक जा सकती हैं।

अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि गर्म और शुष्क मौसम में यह बूंदें तेजी से वाष्पित होकर एरोसोल कणों में बदल जाती हैं जो लंबी दूरी तक संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं। उसमें कहा गया है कि ये छोटे कण फेफड़ों में अंदर तक प्रविष्ट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि मास्क लगाने से एरोसोल कण के जरिए वायरस का प्रसार होने की संभावना प्रभावी रूप से कम होती है।

फल पकने की खबर देने वाली चीड़िया

देवाशीष

हिमालयी क्षेत्रों में इस समय रातों में एक चिड़िया खूब सुरीली तान देती है। इसकी चार लड़ियोंवाली सीटी दिन ही नहीं देर रात तक गूंजती है। पहाड़ के लोगों से पूछेंगे तो वे बताएंगे इस चिड़िया का नाम काफल-पाको है। पहाड़ का जंगली फल काफल इस समय खूब पक रहा है और लोग मानते हैं कि चिड़िया अपनी सुरीली तान से लोगों को काफल पकने की सूचना देती है।

कम दिखनेवाली और ज्यादा सुनायी देनेवाली इस इंडियन कुक्कू का वैज्ञानिक नाम कुकुलस माइक्रोप्टेरस है। गर्मियों और मानसून सीजन में मध्य भारत से उत्तरी भारत तक प्रवास करने वाली चिड़िया का असल ठिकाना पता लगाना, वैज्ञानिकों के लिए अब भी एक चुनौती है। लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ इनडेन्जर्ड स्पीसीज मैनेजमेंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुरेश कुमार कहते हैं कि इंडियन कुक्कू समर विजिटर है। गर्मियों में काफल पकने का समय ही इसके पहुंचने का समय होता है। मानसून खत्म होने के साथ ही ये लौट जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए अब भी ये अध्ययन का विषय है कि इंडियन कुक्कू लौटकर कहां जाती है। इस दौरान ये यहां अपने बच्चों को जन्म देती है। लंबी दूरी तय करने के बाद जब ये चिड़ियां पहुंच जाती

हैं तो अपनी आवाज से अपने क्षेत्र का निर्धारण करती हैं।

सुरेश बताते हैं कि दूसरी कुक्कू को आगाह भी करती हैं कि ये उनका इलाका है। अपने साथी को आकर्षित करने के लिए भी इनकी सीटी गूंजती है। इनकी खास बात ये है कि कोयल की तरह ये भी अपने अंडे दूसरी चिड़िया के घोंसले में डालती है। बैबलर चिड़िया जिन्हें झुंड में रहने की वजह से सात भाई या सात बहन भी कहा जाता है, कुक्कू ज्यादातर इन्हीं के घोंसले में अपने अंडे रखती है। ये प्रकृति की अनूठी बात है कि कुक्कू अपने अंडे ठीक वैसा ही तैयार करती है, जैसे अंडे बैबलर के होते हैं। आश्चर्यजनक ये भी है कि बैबलर अपने और कुक्कू के अंडे में फर्क नहीं कर पाती। उनके अंडे और बाद में उसमें से निकले चूजों का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे उसके खुद के बच्चे हों। जबकि कुक्कू और बैबलर देखने में बिलकुल अलग होते हैं।

इंडियन कुक्कू की सम्मोहक आवाज भी उसके आने के एक-दो महीने तक ही सुनायी देती है। पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़े इसका प्रिय भोजन हैं। इस तरह उनकी आबादी को नियंत्रित कर, पारिस्थितकीय तंत्र में ये चिड़िया अपनी अहम भूमिका निभाती है। इंडियन कुक्कू के साथ ही यूरेशनियन, हिमालयी, पाइड (चातक) समेत कई तरह की कुक्कू चिड़िया अलग-अलग रंग और प्रजाति के साथ मौजूद हैं।

चातक चिड़ियां भी दो-तीन रोज पहले यहां पहुंच चुकी हैं। उनके दिखने का मतलब होता है कि मानसून आने ही वाला है। लोककथाओं का हिस्सा रही चातक चिड़िया दिखने के बाद किसान खेत तैयार करने लगते हैं कि अब बारिश होगी। वैज्ञानिक भी इस बात से नहीं इंकार करते। सुरेश बताते हैं कि इन्हीं चातक चिड़िया पर इस बार एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाने की तैयारी है। इनकी ट्रैकिंग स्टडी की जाएगी। ट्रांसमीटर सेटेलाइट के जरिये ये सूचना देगा कि ये चिड़िया किन रास्तों से गुजरती हुई, कहां लौटती हैं। चातक के बाद अन्य कुक्कू चिड़िया पर भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा।

काफल-पाको चिड़िया की लोककथा

पहाड़ों में मानते हैं कि एक गरीब मां ने बड़ी मेहनत से जंगल से काफल जुटाए कि इसे बेचकर दो पैसे मिलेंगे। दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम होगा। काफल की टोकरी की देखभाल की जिम्मेदार मां ने अपनी नन्ही बेटी को सौंपी और खुद मवेशियों के लिए चारा लाने जंगल चली गई। धूप में रखे काफल सिकुड़ गए। मां जंगल से लौटी तो उसे टोकरी में काफल कुछ कम लगे। वहीं उसकी बेटी सो रही थी। उसने नींद में लेटी बच्ची को ही ज़ोर से मारा। बच्ची की मौत हो गई। सदमे से कुछ दिनों बाद मां की भी मौत हो गई। यही मां-बेटी काफल-पाको चिड़िया बन गईं। जब काफल पकते हैं, मां चिड़िया कहती है ''काफल-पाको'', बेटी चिड़िया बोलती है ''मैं नि चाख्यो (मैंने नहीं चखा)''। यही धुन चिड़िया की आवाज़ से सुनायी देती है।

काफल का परिचय

काफल उत्तराखंड का जंगली फल है। चटक लाल-काले रंग का ये फल देखने में खूबसूरत और खट्टे-मीठे स्वाद वाला होता है। इसका औषधीय इस्तेमाल भी खूब होता है। पहाड़ों में ये आर्थिकी का ज़रिया भी है। जंगलों में चिड़ियों-जानवरों के भोजन के काम आता है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।